नीति का
संक्षिप्त विवरण

शहरी विकास में लिंग और विकलांगता का समावेश

UNITED NATIONS
INDIA

सत्यमेव जयते
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

NIUA
National Institute of Urban Affairs

नीति का
संक्षिप्त विवरण

शहरी विकास में लिंग और विकलांगता का समावेश

UNITED NATIONS INDIA

सत्यमेव जयते
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

NIUA
National Institute of Urban Affairs

यह नीति संक्षिप्त “एसडीजी विशेष रूप से एसडीजी” के कार्यान्वयन में लिंग और दिव्यांगता का मुख्य रूप से समावेशन पर रा.न.का.सं. एवं यू.एन. के बीच संयुक्त प्रयास के अंतर्गत “शहरी विकास में लिंग और दिव्यांगता समावेशन” पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी द्वारा समर्थित हैं।

UNPRPD MPTF
Partnership on the Rights of Persons with Disabilities

नीति का यह मसौदा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, कर्नाटक, की स्नेहा विशाखा, दामिनी घोष और नम्रता मुरुगेशन द्वारा लिखा (तैयार) गया है।

V | D H | Centre for Legal Policy

डिजाइन और ग्राफिक्स:
कुनाल अग्निहोत्री और रा.न.का.सं. डिजाइन टीम

अनुवाद:
इस नीति संक्षिप्त का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद (ईभाषा सेतु) मनीष गौर द्वारा किया गया है।

डिस्क्लेमर: इस दस्तावेज़ में व्यक्त किए गए निष्कर्ष, विश्लेषण, विचार, विकल्प और सिफारिशें लेखक की हैं जो हितधारकों के परामर्श और गहन माध्यमिक अनुसंधान की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और आवश्यक नहीं कि भारत में रा.न.का.सं. और यू.एन. का प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्ध करती हो। भारत में रा.न.का.सं. या यू.एन. की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत, एक पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

2022 में प्रकाशित
कॉपीराइट- भारत में संयुक्त राष्ट्र और रा.न.का.सं. 2022

विषय-वस्तु

कार्यकारी सारांश ..... page 1

I. परिचय.....पृष्ठ 4

II. उद्देश्य.....पृष्ठ 6

III. सीमाएं.....पृष्ठ 6

IV. कार्यप्रणाली.....पृष्ठ 7

V. मुख्य निष्कर्ष.....पृष्ठ 8

क. शहरों में लिंग समावेशन की चुनौतियां

ख. शहरों में विकलांगता समावेशन की चुनौतियां

ग. विकलांग महिलाओं और लड़कियो द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

घ. विचार योग्य मुद्दे

1. शहरी नीति और योजनाओं में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के विचारों की कमी
2. शासन में चुनौतियां
3. कार्यान्वयन में अंतराल
   - i. निर्मित माहौल
   - ii. परिवहन और आवाजाही
   - iii. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
   - iv. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
4. समन्वय और साइलो एजेंसियों की कमी
5. संवेदीकरण, जागरूकता और क्षमता निर्माण का अभाव

VI. लिंग और विकलांगता समावेशी विकास में उभरते क्षेत्र.....पृष्ठ 17

VII. सिफारिशें.....पृष्ठ 18

क. राष्ट्रीय स्तर

ख. राज्य स्तर

ग. निगम स्तर

घ. सामान्य सिफारिशें

1. तकनीकी
2. सामाजिक
3. आर्थिक
4. आवाजाही

संदर्भ.....पृष्ठ 25

अभिस्वीकृति.....पृष्ठ 28

संकेताक्षर की सूची

एएसडी	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
बीबीएमपी	ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका
बीएमटीसी	बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सीईडीएडब्ल्यू	कंवेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन
डीपीओ	डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गनाइज़ेशन (विकलांग जन संगठन)
डीआरआर	डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन (आपदा जोखिम न्यूनीकरण)
आईसीएफ	इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ (कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण)
आईसीटी	इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)
एलजीबीटी	लेसबियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर
एनसीपीईडीपी	नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्पलॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र) le
एनयूटीपी	नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी (राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति)
आरपीडब्ल्यूडी	राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार)
आरपीडब्ल्यूडीए	राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016 (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016)
एसडीजी	सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (सतत विकास लक्ष्य)
एसइडब्ल्यूए	सेल्फ-एम्पलॉइड वुमन्स असोसिएशन (स्व-रोज़गार महिला संघ)
एसआईपीडीए	स्कीम फॉर इमप्लिमेंटिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 1995 (विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम, 1995)
टीओडी	ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट
यूएमटीए	यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी
यूएन	यूनाइटेड नेशन (संयुक्त राष्ट्र)
यूएनसीआरपीडी	यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन)
यूएनडीपी	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)
डब्ल्यूएसएच (वॉश)	वॉटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन

कार्यकारी सारांश

दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी (55 प्रतिशत) शहरी इलाकों में रहती है। ऐसा अनुमान है कि यह आंकड़ा 2050[1] तक 68 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। शहरों की जबरदस्त वृद्धि और शहरीकरण की दर शहरी विकास के कई क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियां पैदा कर रही है। इनमें आवास, परिवहन और आवाजाही, पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH), सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, पोषण और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स्थिरता और सुरक्षा शामिल हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों, बच्चे और युवा, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, शहरों में रहने वाले गरीब, अनौपचारिक-बस्तियों में रहने वाले लोग, प्रवासी, जैसे अन्य कमजोर समूहों को बेहद गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

> भारत में, महिलाओं की संख्या 48.5 प्रतिशत है और विकलांग व्यक्ति कुल जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत हैं।[2] इस आबादी के भीतर, गरीबी, आयु, धर्म, जाति, वर्ग और जातीयता जैसे कारक शहरों में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों और अन्य लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्करणों की प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से शहरों में या तो समावेश को बढ़ावा दिया जा सकता है या उनके डिजाइन के आधार पर बहिष्करण को स्थिर रखा जा सकता है।

मौजूदा लेखों और शहरी विकास में लिंग और विकलांगता समावेशन के कानूनी और नीतिगत ढांचे की जांच से कुछ प्रमुख मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, जो कुछ इस प्रकार है: शहरों में रहने वाले लोगों की विविधता और उनकी बदलती जरूरतों पर ध्यान न देना, विकेंद्रीकरण, भागीदारी और जन-केंद्रित योजनाओं की कमी। इसके साथ-साथ नीति बहुलता और असंगति, शहरी नियोजन, डिजाइन और शासन पर काम करने वाली एजेंसियों की कमी। इतना ही नहीं सेवा के वितरण के लिए जिम्मेदार अन्य विभागों के साथ आपस में तालमेल की कमी के साथ-साथ लिंग, उम्र और विकलांगता के आधार पर डेटा की कमी भी दिखाई देती है।

जबकि लैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन को वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लक्ष्यों के रूप में रेखांकित किया गया है, शहरी संदर्भ में उनकी प्राप्ति मुख्य रूप से राज्य और नगरपालिका प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में है। नीति का यह संक्षिप्त विवरण शहर में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न विशिष्ट परेशानियों और दिक्कतों पर प्रकाश डालता है। यह समावेशी और भागीदारी नियोजन दृष्टिकोण की वकालत भी करता है, जो लिंग के आधार पर बदल जाते हैं। इनका उद्देश्य शहरों में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों का नैतिक और सार्थक समावेश है। यह विवरण प्रणालीगत सुधार के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की वकालत करता है, जिसमें स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने, विकेंद्रीकृत भागीदारी योजनाओं और डिजाइन को बढ़ावा देने, योजना और शासन में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संवेदीकरण आदि शामिल हैं। इसके साथ-साथ इसमें शहरों में काम कर रहे नागरिक, निजी क्षेत्र, पड़ोस और

[1] यूएन डीईएसए 2018

[2] जनगणना 2011

सामुदायिक समूहों में प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी और नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं।

इसके अलावा, नारीवादी और लिंग परिवर्तनकारी नियोजन दृष्टिकोण अपनाना, आयु-प्रतिक्रियात्मक, विकलांगता-केंद्रित पहल विकसित करना, जिसमें सभी शहरी विकास परियोजनाओं और सेवा वितरण में सार्वभौमिक डिजाइन मानदंड शामिल हैं और साथ ही इसमें समावेश की पहल के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिमान्य खरीद नीतियां भी शामिल हैं। यह समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों की जरूरतों के लिए सुरक्षित, सुलभ और किफायती शहरी परिवहन और आवाजाही के बुनियादी ढांचे को डिजाइन करना, गैर-मोटर चालित परिवहन और अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जिन्हें उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे व्यापक WASH कवरेज के ज़रिए सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराना जो मुफ्त और सुलभ हों, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना जो महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और सस्ती हों।

I. परिचय

सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे में, विश्व के नेताओं ने वर्ष 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने का संकल्प लिया है, जिसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों (एसडीजी 5) को सशक्त बनाना, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी बनाना, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ (एसडीजी 11) बनाना, स्पष्ट रूप से लैंगिक समानता और अक्षमता को आवश्यक क्रॉस-कटिंग मुद्दों के रूप में पहचानना शामिल है। **एसडीजी 11 में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच के द्वारा 'सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, सस्ते, हरे-भरे सार्वजनिक स्थान के साथ-साथ टिकाऊ परिवहन प्रणाली प्रदान करने में उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान देना शामिल है।** एसडीजी गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच, हिंसा से सुरक्षा और स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक और स्थानिक न्याय, पहुंच, गतिशीलता, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा, सुरक्षित और किफायती आवास, बुनियादी सेवाओं पर जोर देते हैं। इसके साथ ही इन लक्ष्यों में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों पर ध्यान देने के साथ-साथ भागीदारी निर्णय लेने के साथ रोजगार के अवसर और कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इन लक्ष्यों में से प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और समावेशी शहरों के निर्माण से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

पहुंच पर काम कर रहे नारीवादी और विकलांगता पर शोध करने वाले विद्वानों का तर्क है कि शहरों में रहने वाले लोगों की विविधता पर विचार की कमी के कारण लिंग और विकलांगता के आधार पर होने वाला बहिष्करण शहरी वातावरण में सामाजिक और स्थानिक तौर पर जन्म लेता है।[3] नया शहरी एजेंडा (2016) अधिकारों पर आधारित होने के साथ-साथ शहरी विकास के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण की बात करता है। यह उम्र और लिंग के अनुकूल है, ग्रह संवेदनशील है, प्रासंगिक और साक्ष्य-आधारित है। इसके साथ-साथ ही इसकी नींव विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो न्यायसंगत और भागीदारी प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होती है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें या सबको सम्मिलित करें' और 'आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए योजना तैयार करना' जैसी अवधारणाओं पर आधारित हैं, जो शहरों के संदर्भ में मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन के प्रति प्रतिबद्धताओं की ओर ज़ोर देते हैं।

लैंगिक समानता, पहुंच और शहरी विकास में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के महत्व की व्यापक मान्यता के बावजूद, शहरी डिजाइन और योजनाओं को तैयार करने प्रक्रिया में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों को अक्सर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। नारीवादी और विकलांगता-केंद्रित परिप्रेक्ष्य की अनुपस्थिति, भागीदारी योजना प्रक्रियाओं, शहरी योजनाकारों, चिकित्सकों और नगरपालिका अधिकारियों के बीच जागरूकता की कमी, उपकरणों और विशेषज्ञता की अनुपस्थिति, कानूनी जनादेश की कमी जैसे विभिन्न कारक लिंग के प्रभावी कार्यान्वयन और शहरों में विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में बाधा डालते हैं।

शहरों में लिंग और विकलांगता के आधार पर होने वाले बहिष्करण से निपटने में 'आदर्श ' की धारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसकी कल्पना पुरुष और सक्षम शरीर के रूप में की जाती है, और 'अन्य' को महिला के रूप में या विकलांग या दोनों के रूप में सामने रखा जाता है।[4] दुनिया में आज तक जिस भी तरह से शहरो का डिजाइन और विकास हुआ है उसमें पितृसत्तात्मक लिंग भूमिकाएं और असमानताएं दिखती हैं।[5] यह ज़ोनिंग प्रथाओं की विशेषता है. जो सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कार्यस्थलों को निजी क्षेत्र जैसे आवास से अलग करती है, और इसी कारण से महिलाओं और बच्चों को भूमि उपयोग नीतियों के केन्द्र में नहीं रखा जाता है। शहरी गतिशीलता की नीतियों ने देखभाल करने वाली महिलाओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की तुलना में पुरुष श्रमिकों की गतिशीलता को प्राथमिकता दी जाती है।[6] इसके परिणामस्वरूप ऐसे शहरी स्थानों का निर्माण हुआ है, जहां महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित या सहज महसूस नहीं करती हैं, और साथ ही

[3] विशाखा 2021

[4] फड़के, खान, रानाडे 2011

[5] वीज़मैन 1981

[6] फेनस्टीन और सेवरोन 2005

बच्चे, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्गों और असंख्य अन्य कमजोर समूहों को ध्यान में न रखते हुए शहरों की योजना और उसका डिजाइन तैयार किया गया है।[7]

विश्व स्तर पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को इसके सामान्य सिद्धांतों में से एक के रूप में शामिल किया गया है और साथ ही स्पष्ट रूप से महिलाओं, लड़कियों और विकलांग बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग और विकलांगता की धुरी पर होने वाले जटिल भेदभाव को पहचाना गया है। इसके साथ-साथ इसमें महिलाओं के पूर्ण विकास, उन्नति और सशक्तिकरण की मांग भी की गई है। **राष्ट्रीय स्तर पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPWDA), एक प्रगतिशील अधिकार आधारित शासन, समानता के अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के भेदभाव के खिलाफ और दूसरों के जैसे ही समान अधिकार की गारंटी देता है।[8] यह विशेष रूप से सरकारों के सभी स्तरों को, यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने के लिए जिम्मेदार बनाता है कि विकलांग महिलाएं और बच्चे दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें।**[9]

इस संदर्भ में लैंगिक असमानता की चुनौतियों में महिलाओं और लड़कियों, विशेषकर शहरों में रहने वाली विकलांग महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियां शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें पहुंच की कमी, लोगों पर लगने वाले लांछन और विकलांगता से जुड़ी शर्म, शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच की कमी, स्वास्थ्य, यौन और प्रजनन अधिकारों के संदर्भ में स्वायत्तता से वंचित होना, सलुभ स्वच्छता सुविधाओं की कमी सहित प्रयाप्त WASH बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति और दूसरों के बीच लिंग-तटस्थ सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

जबकि लिंग और विकलांगता समावेशन के उद्देश्य से हस्तक्षेपों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है, इसके बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक और दृष्टिकोण संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो संदर्भों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जहां विकलांगता समावेशन के उद्देश्य से किए गए हस्तक्षेप, जो परिवारों पर बोझ को कम करते हैं, सामुदायिक स्तरों पर अधिक स्वीकार्य होते हैं। इसके साथ ही लिंग शक्ति संबंध गहराई से जुड़े होते हैं और इसमें परिवर्तन लाना अधिक कठिन हो सकता है।[10] जब विकलांग महिलाओं और लड़कियों की बात आती है, वे लिंग के साथ-साथ विकलांगता से जुड़े संयुक्त असुविधा का अनुभव करती हैं, और इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। साथ ही सहायक उपकरणों तक कम पहुंच[11], लाछंन के कारण मिलन वाली पुनर्वास सुविधाएं, महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों या सेवा प्रदाताओं की कमी, यात्रा प्रतिबंध, लोगों के बीच सीमित संसाधन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। परिवार और समुदाय की सांस्कृतिक धारणाओं के लिए पारंपरिक लिंग मानदंडों का महत्व इन मानदंडों पर सवाल उठाना चुनौतीपूर्ण और कठिन बना देता है।[12] इसके लिए शहरी विकास प्राथमिकताओं में न केवल समावेश बल्कि असमान लिंग के परिवर्तन पर जोर देने के साथ भारतीय शहरों में असमान लिंग संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[7] विश्व बैंक 2020

[8] भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, खंड 3

[9] भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 4

[10] वॉटर ऐड 2017

[11] विश्व बैंक 2011

[12] वॉटर ऐड 2017

II. उद्देश्य

नीति का यह संक्षिप्त विवरण विशेष रूप से भारतीय शहरों में सुरक्षित, समावेशी, लचीले और टिकाऊ निर्माणों के एसडीजी 11 के कार्यान्वयन में लिंग और विकलांगता समावेशन के प्रयासों को उजागर करता है। इस विवरण में शहरों में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट दिक्कतों की तैयार रूपरेखा को बताया गया है। इसके साथ-साथ इसमें प्राथमिकता के आधार पर होने वाले हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है और भागीदारी नियोजन दृष्टिकोण, लिंग-परिवर्तनकारी योजना के लिए तरीकों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले और शहरों में विकलांग और सामान्य महिलाओं और लड़कियों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के नैतिक और सार्थक समावेश के उपायों को बताया गया है।

यह विवरण निम्नलिखित तरीकों द्वारा लैंगिक और विकलांगता समावेशी शहरी विकास को आगे बढ़ाने के उपायों को बताता है और उनकी जांच करता हैः

III. सीमाएं

अध्ययन के दायरे की सीमाओं के कारण, नीति का यह संक्षिप्त विवरण विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल माता-पिता, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों और चुनौतियों को कवर नहीं करता है। इसमें जाति और धर्म आधारित भेदभाव का सामना करने वाले, यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक जिनमें एलजीबीटी समूहों के लोग, ऐसे अन्य समूहों के प्रवासी भी शामिल हैं। उनके सामने विशेष रूप से, सुरक्षित और किफायती आवास तक पहुंच, किराए के आवास में भेदभाव, रोजगार के अवसरों की कमी, राजनीतिक भागीदारी में बाधाएं और स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल जैसे सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां शामिल हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच शिक्षा और स्वच्छता जैसी सुविधाए भी आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। इन समूहों में से प्रत्येक को शहरी विकास प्राथमिकताओं में शामिल करने और उनका प्रतिनिधित्व करने हेतु लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने के लिए विशिष्ट विचार-विमर्श और उसके बाद, सावधानीपूर्वक शोध की आवश्यकता है।

1. शहरी विकास की प्राथमिकताओं में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता और पहुंच के महत्व पर प्रकाश डालना;
2. शहरों में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से अदृश्य विकलांगता वाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों और कमजोरियों को रेखांकित करना;
3. प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से सुरक्षित, समावेशी, लचीले और टिकाऊ शहरों के निर्माण के उपायों की पहचान करना; तथा
4. लैंगिक और विकलांगता-समावेशी शहरों के निर्माण की दिशा में प्रगति के लिए शहरी योजनाकारों, व्यवसायियों, नगरपालिका अधिकारियों और सरकारी संस्थानों के लिए कार्यान्वयन योग्य उपायों का सुझाव देना।

हितधारकों के रूप में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ भागीदारी नियोजन प्रक्रियाओं को पेश करने वाला एक चित्रण।

IV. पद्धति / कार्य विधि

इस नीति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, लेखों की समीक्षा, डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर्श सहित अनुसंधान विधियों और प्रक्रियाओं का मिश्रण अपनाया गया था। शहरी संदर्भ में लिंग और विकलांगता समावेशन पर प्रासंगिक हितधारको द्वारा विकसित संस्थागत, कानूनी और नियामक वातावरण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और मानकों के स्थितिजन्य विश्लेषण के हिस्से के रूप में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू), यूएनसीआरपीडी, एसडीजी, न्यू अर्बन एजेंडा आदि की समीक्षा की गई। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ-साथ दक्षिण एशिया के संदर्भ में प्रासंगिक लिंग और विकलांगता समावेशन पर अन्य विकास संगठनों द्वारा विभिन्न अनुसंधान और नीति दस्तावेजों की भी जांच की गई। इसके अलावा, भारत में आरपीडब्ल्यूडीए जैसे कानूनों और शहरी नियोजन और विकास से संबंधित कानूनों की समीक्षा की गई ताकि शहरी विकास में लिंग और विकलांगता समावेशन के विस्तार और शहरों में सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए शासन के विभिन्न स्तरों पर कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप के क्षेत्रों को उजागर किया जा सके। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण किया गया था। इस विवरण को तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट, योजनाकारों, विकलांग लोगों के संगठनों (डीपीओ) के प्रतिनिधियों, विकलांग व्यक्तियों और विषय-वस्तु विशेषज्ञों सहित हितधारकों के समूहों से परामर्श लिया गया। इसके अलावा, नीति के मसौदे की कई समीक्षकों द्वारा उनके सहकर्मियों से समीक्षा भी कराई गई थी। गोलमेज विशेषज्ञ चर्चा और सत्यापन कार्यशाला में भी इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और इसे मान्यता दी गई, जिसमें सरकार और नागरिक समाज के हितधारक शामिल थे, और साथ ही इसमें विकलांग व्यक्तियों के संगठन, महिला संगठन, आर्किटेक्ट, विकलांगता के विशेषज्ञ और वकालत समूहों के व्यक्ति भी शामिल थे।

> “महामारी के बाद घरों से बाहर निकल कर काम करने वाली महिलाओं की संख्या कम हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की पहुंच के लिए सुरक्षा अक्सर पहली ज़रूरत होती है। विकलांग महिलाओं के लिए, सार्वजनिक स्थान दोगुने खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित पुरुष बस स्टॉप पर जा सकते हैं और आसानी से अपनी मंज़िल का पता पूछ सकते हैं। जब महिलाएं ऐसा करती हैं, तो यह यौन उत्पीड़न के लिए एक संभावित साइट बन जाती है। तथ्य यह है कि बहुत सारी महिलाएं बस स्टॉप का उपयोग करती हैं, इसका मतलब है कि उन्हें टॉयलेट और विश्राम स्थलों के भी उपयोग की ज़रूरत होगी और विकलांग बच्चों के साथ भी ऐसा ही है क्योंकि देखभाल करने वालों को बच्चों को बाहर ले जाने की जरूरत होती है, वे भी भारत में प्रमुख रूप से महिलाएं ही होंगी। इसलिए यह तथ्य कि शहर महिलाओं के लिए सुलभ नहीं है, इसका अर्थ यह भी हुआ कि इससे विभिन्न समूह प्रभावित होते हैं।"
>
> -वास्तुकार [21 मार्च, 2022 को विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित फोकस ग्रुप डिस्कशन]

V. मुख्य निष्कर्ष

क. शहरों में लिंग आधारित समावेशन की चुनौतियां

शहरों में, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा एक वास्तविकता है। विश्व स्तर पर, 2017 में लगभग 87,000 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिनमें से आधे से अधिक (58 प्रतिशत) की हत्या उनके साथियों या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी। इससे घर 'किसी महिला के मारे जाने की सबसे संभावित जगह' बन गया है।[13] 2018 के वैश्विक अनुमानों से संकेत मिलता है कि 15-19 वर्ष की आयु की चार किशोर लड़कियों में से लगभग हर एक को अपने साथी के द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा है।[14]

> लगभग 33 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक स्तर पर शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। हालांकि, दुर्व्यवहार का सामना करने वाली विवाहित महिलाओं में से केवल एक-चौथाई ही शारीरिक और गंभीर चोटों की रिपोर्ट करती हैं और केवल 14 प्रतिशत महिलाएं हिंसा को रोकने के लिए मदद मांगती है।[15]

दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर भूमि और संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 15 प्रतिशत है।[16] अध्ययनों से पता चलता है कि घर या जमीन पर महिलाओं का स्वामित्व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से वैवाहिक हिंसा के जोखिम को काफी कम कर देता है। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को पुरुष साथी के द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचने में मदद करता है। 71 प्रतिशत महिलाएं जो किसी संपत्ति की अधिकारी थी और उन्होंने लंबे समय तक शारीरिक हिंसा का सामना किया था, उन्होंने सफलतापूर्वक अपना घर छोड़ दिया, और वहीं वे महिलाएं जो किसी संपत्ति की अधिकारी नहीं थी केवल 19 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसा कर पाईं।[17]

इसके अलावा, अपर्याप्त और दुर्गम WASH सुविधाएं सभी महिलाओं और लड़कियों को हिंसा के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरों की तरफ धकेलती हैं। शहरों में पर्याप्त WASH सुविधाओं की कमी महिलाओं की सुरक्षित और पर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता को बनाए रखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। सांस्कृतिक पाबंदियों के कारण यह अत्यधिक उपेक्षित मुद्दा है। इन गंभीर कारणों की वजह से महिलाओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार और लड़कियों के यौवन की उम्र तक पहुंचने के बाद शिक्षा को बंद करने या छोड़ने जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।[18] यह विशेष रूप से अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों से संबंधित हैं, जिनकी स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक पहुंच बहुत सीमित होती है। इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों को निर्जलीकरण और पेशाब रोकने के कारण मूत्राशय और मूत्र पथ के संक्रमण जैसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।[19]

2012 में पेशाब करने के अधिकार अभियान द्वारा किए गए एक अध्यन में पाया गया कि जहां मुंबई में पुरुषों के लिए 2,466 से अधिक मूत्रालय बनाए गए थे, वहीं महिलाओं के लिए कोई मूत्रालय नहीं बनाया गया था। यह योजना बनाने वाले लोगों की मानसिकता को उजागर करता है, जो यह मानती है कि महिलाएं कार्यबल के हिस्से के रूप में सार्वजनिक स्थानों को इस्तेमाल करने की अधिकारी नहीं है या उन्हें सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित मूत्रालयों का उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके

13 यूएनओडीसी 2018
14 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), 2021
15 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), 2021
16 संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (यूएन हैबिटेट) 2020
17 अग्रवाल एंड पांडा 2007
18 विश्व बैंक 2020
19 शैली 2017

अलावा, स्वच्छता से संबंधित वैधानिक ढांचे, उनके दृष्टिकोण में लिंग के आधार पर तटस्थ हैं।[20] इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां स्वच्छता को विशेष रूप से महिलाओं की संबंधित ज़रूरतें और चिंताओं को उजागर या संबोधित किए बिना सभी लिंगों में बराबरी के स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने की एक सामान्य जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती हैं। जबकि महिलाओं के लिए भी समान स्तर पर सुविधाएं देने से संभवतः शहरों में स्वच्छता से संबंधित उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को कम करने में मदद मिलती है।[21]

> भारत में महिलाओं के यात्रा पैटर्न को जटिल 'ट्रिप-चेनिंग'[22] द्वारा यानी एक यात्रा के भीतर एक या एक से अधिक गंतव्यों को मिलाकर चिन्हित किया जाता है। महिलाएं, मुख्य रूप से घरेलू और देखभाल का काम बिना वेतन के करती हैं। भुगतान किए गए काम के अलावा, छोटी और अधिक यात्राएं करती हैं, जिससे उन्हें बच्चों को लाने, काम करने, दुकान करने या अन्य पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए अपनी यात्रा की दिशा को बार-बार बदलने और अपनी यात्रा को बीच-बीच में रोकने की ज़रूरत पड़ती है।[23]

यह महिलाओं के लिए यात्रा को महंगा बनाता है, क्योंकि वे इस तरह की चेन रूपी यात्रा के दौरान कई एकल किराए के टिकट या यात्रा में लगने वाले किराए का भुगतान करती हैं। सुलभ और सुरक्षित आवाजाही संरचना की कमी, विशेष रूप से सार्वजनिक बस संरचना, शहरों में महिलाओं के साथ-साथ देखभाल करने वालों, बच्चों या परिवार के सदस्यों के लिए, विकलांगों के लिए आवाजाही को बेहद मुश्किल बना देती है। सुलभ आवाजाही के बुनियादी ढांचे की कमी और जर्जर अवस्था में मौजूदा बुनियादी ढांचा विकलांग महिलाओं और लड़कियों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देता है, जिससे वे शहरों में दुर्घटनाओं, हिंसा और सुरक्षा की कमी के उच्च जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

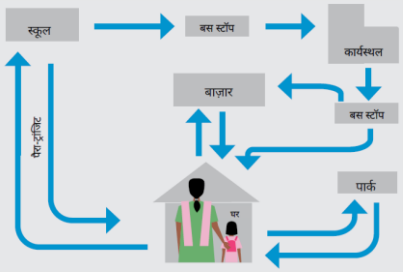

ट्रिप-चेनिंग को दर्शाने वाला एक चित्रण, जिसमें एक या अधिक गंतव्यों को एक यात्रा के भीतर मिला दिया जाता है।

महिलाओं के शहरी आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद,[24] शहरी स्थानीय संस्थानों या प्रबंधक, यानी महिलाओं की जरूरतों पर विशेषज्ञता रखने वाले डोमेन-विशिष्ट कार्यक्रमों या एजेंसियों जैसे महिला और बाल विकास विभाग के बीच 'लिंग' एक मुख्य आधार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम और नीतियां बिना लिंग परिप्रेक्ष्य के शुरू की गई हैं। इसके अलावा, शहरों में लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी की चल रही समस्या से निपटने के लिए, तकनीकी हस्तक्षेप (जैसे सीसीटीवी) का उपयोग करने वाले संरक्षणवादी उपायों को अक्सर संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है, वो भी बिना गहन विश्लेषण[25] के कि कैसे शहरी नियोजन और परिवहन प्रणालियों को लिंगबद्ध किया जाता है।

ख. शहरों में विकलांगता समावेशन की चुनौतियां

> संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति विकासशील देशों में रहते हैं[26], जिनमें से 5 में से 3 विकलांग व्यक्ति महिलाएं हैं और विकलांग बच्चों और वयस्कों में अधिकतम संख्या गरीबों की हैं।

20 पवार 2021
21 कूनन एस 2019
22 विश्व बैंक 2020।
23 शाह, विश्वनाथ, व्यास और गडेपल्ली 2017
24 खोसला 2009।
25 शाह, विश्वनाथ, व्यास और गडेपल्ली 2017
26 यूएनडीपी 2018

इसके अलावा, विकलांगता और उच्च निरक्षरता, बेरोजगारी और कम मजदूरी के बीच एक सीधा संबंध है, जो विकलांगता के साथ-साथ गरीबी के जोखिम को भी बढ़ाता है। विकलांगता से जुड़ी उच्च आर्थिक और सामाजिक लागते भी हैं, जो अक्सर पहुंच से बाहर वाले वातावरण के कारण सीधे उत्पन्न होती हैं। इससे विकलांग व्यक्तियों को बदतर शैक्षिक और श्रम बाजार के बुरे प्रभाव और उच्च गरीबी दर का सामना करना पड़ता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए, शहर तक पहुंच उन्हें बहुत से अधिकार देती है-शहरी स्थानों तक पहुंच उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के पूर्ण इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में, यूएनसीआरपीडी और आरपीडब्ल्यूडीए दोनों विकलांग व्यक्तियों के बाधा मुक्त, सुलभ शहरी स्थानों के अधिकार को मान्यता देते हैं।[27] विकलांग व्यक्ति कई भौतिक, सामाजिक-आर्थिक, व्यवहारिक और संरचनात्मक बाधाओं को सामना करते हैं जो उनकी इस भागीदारी को सीमित करते हैं। इसके साथ ही शहरों में बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, आदि किसी न किसी प्रकार की असमर्थता का अनुभव करते हैं, जिस कारण उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है।

यूएनसीआरपीडी द्वारा दी गई विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा के अनुसार जो लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मस्तिष्क-संबंधी असमर्थता का सामना कर रहे हैं उन्हें विकलांग माना जाएगा। इन असमर्थताओं से उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण दूसरों के साथ बातचीत करने में, दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती हैं।[28] अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कार्य, अक्षमता और स्वास्थ्य (आईसीएफ) की विचारधारा[29] विकलागंता को एक 'जैव-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मॉडल' के रूप में देखती है,[30] जो एक अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है और साथ ही विकलांगता को स्वास्थ्य की स्थिति और पर्यावरण के बीच एक नकारात्मक परस्पर क्रिया से उत्पन्न होने के रूप में पहचानती है। यह विचारधारा संरचनात्मक, स्वास्थ्य, सामाजिक, व्यक्तिगत, मनोवृत्ति और संस्थागत स्थितियों की भूमिका को रेखांकित करती है। इसमें जटिल और विविध अनुभवों की एक विस्तृत श्रृखला शामिल है, जो हानि के प्रकार के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकती है। विकलांगता की इस समझ के लिए समावेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जो स्थानीय संदर्भ, समुदाय और अन्य कारकों जैसे कि सामर्थ्य, सुविधा, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक संदर्भ के लिए विशिष्ट व्यक्ति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, विकलांग महिलाओं और लड़कियों को पहुंच में बाधाओं के अलावा लैंगिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनकी पहुंच को नारीवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ विकलांगता न्याय के दृष्टिकोण से भी संबोधित करने की आवश्यकता है। शहरों के संदर्भ में, निर्मित पर्यावरण, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं, परिवहन और आवाजाही, आवास, रोजगार सृजन, प्रशिक्षण और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक बचपन में किए जाने वाले हस्तक्षेप कमजोर लोगो के विभिन्न समूहों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं और यह महिलाओं, विकलांग लड़कियों और सामान्य लड़कियों के साथ-साथ अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए लक्षित हस्तक्षेप की कुछ प्रमुख जगहें हैं। यह यूएनसीआरपीडी के साथ-साथ आरपीडब्ल्यूडीए के तहत निर्धारित ढांचे में परिलक्षित होता है।

जबकि शहरों में विकलांगता समावेशन की नीतियों ने पहुंच को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में लिया है, और वैसे भी विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच की कल्पना और कार्यान्वयन के साथ गंभीर समस्याएं हैं।[31] उन लोगों की व्हीलचेयर सुलभता पर जोर दिया गया है, जो लोकोमोटर विकलांगता के साथ-साथ अन्य प्रकार की अक्षमताओं, विशेष रूप से अदृश्य अक्षमताओं जैसे बहरापन, बौद्धिक या 'छिपी' या मनोसामाजिक अक्षमताओं (जैसे मानसिक बीमारियों, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या एएसडी, डिस्लेक्सिया और अन्य) से पीड़ित हैं। इसके अलावा, जहां सीमित सुलभ डिजाइन समाधान लागू किए जाते हैं जैसे कि कर्ब कट्स, लोगों के लिए टैक्टाइल पेविंग, जमीनी स्तर पर संवेदीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी के कारण कार्यान्वयन अक्सर अधूरा या दोषपूर्ण होता है। इसके अलावा, विकलांगता समावेशन नीतियों को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, जो विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी पर जोर देते हुए, लिंग, आयु, गरीबी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भ जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करे कि कमजोर समूहों के विकलांग व्यक्तियों को ऐसे हस्तक्षेपों से बाहर नही रखा जाए।

इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं, परिवहन और गतिशीलता प्रणालियों सहित मौजूदा दुर्गम निर्मित स्थानों की रेट्रोफिटिंग, वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर, विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियो की विविध

[27] अनुच्छेद 9, यूएनसीआरपीडी और धारा 40, आरपीडब्ल्यूडीए।

[28] अनुच्छेद 1, यूएनसीआरपीडी

[29] विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्ययूएचओ), कार्य पद्धति, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, 2002

[30] विश्व बैंक 2011

[31] विशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस्ततीदार 2022

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जैसे कि ये सुविधाएं सुरक्षित, सुलभ, उपयोग में आसान और सस्ती हों। हालांकि, मौजूदा दुर्गम बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार करना काफी महंगा सौदा है।[32] दूसरी ओर, सार्वभौमिक डिजाइन, सार्वभौमिक पहुंच के उद्देश्य से, उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों और सेवाओं के डिजाइन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे सभी लोगों द्वारा संभावित अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सकता है, वो भी अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना।[33] सार्वभौमिक डिजाइन, और इसकी प्रकृति से, किसी विशेष साइट के सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझने के लिए भागीदारी और परामर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। e.[34]

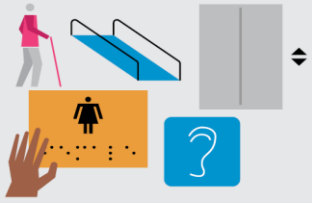

सार्वभौमिक डिजाइन के पहलुओं को दर्शाने वाला एक चित्रण जैसे ब्रेल में दस्तावज, व्हीलचेयर सुलभ रैंप, लिफ्ट जिन्हें योजना प्रक्रिया में अपनाया जाना है।

ग. महिलाओं और विकलांग लड़कियों के सामने चुनौतियां

विश्व विकलांगता रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की संख्या 19.2 प्रतिशत है,[35] जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में विकलांग महिलाएं और लड़कियां अपने लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, जाति, वर्ग, विकलांगता और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के जटिल रूपों का सामना करती हैं।[36] इसके साथ ही वे यौन हिंसा के उच्च जोखिम के स्तर पर हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जो विशेष रूप से गंभीर, बहु या बौद्धिक अक्षमताओं वाली विकलांग महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए बेहद ही गंभीर स्थिति पैदा करती है।[37]

मनोसामाजिक या बौद्धिक अक्षमता वाली महिलाएं, विशेष रूप से, बेहद कलंकित माने जाने वाली और हाशिए पर रहने वाली महिलाएं, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत, पेशेवर और सार्वजनिक रूप से कलंक और भेदभाव का सामना करती हैं।[38] अध्ययनों से पता चलता है कि विकलांग महिलाएं और लड़कियां जिनके पास अक्सर सार्थक पहुंच का अभाव होता है उन्हें तकनीकी रूप से सरकारी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पुनर्वास और रोजगार आदि में शामिल किया गया है।[39] इसके अलावा, लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाएं जिन्हें महिलाओं और लड़कियों को उनके दैनिक जीवन में मनोसामाजिक या बौद्धिक अक्षमताओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उनमें महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है।

> 2004 में उड़ीसा में किए गए एक सर्वेक्षण में,[40] 22.6 प्रतिशत विकलांग महिलाओं को घर पर पीटे जाने की सूचना मिली थी और 12.6 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं और 25 प्रतिशत बौद्धिक रूप से विकलांग महिलाओं के साथ बलात्कार होने की सूचना मिली थी।

इसके अलावा, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं में से 6 प्रतिशत और बौद्धिक और मनोसामाजिक रूप से विकलांग महिलाओं में लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं की जबरन नसबंदी की गई थी। इसके साथ-साथ यह भी पाया गया कि जागरूकता की कमी, नकारात्मक अतीत के अनुभवों के साथ-साथ भेदभावपूर्ण प्रदाता दृष्टिकोण के कारण विकलांग महिलाओं की देखभाल और सेवाओं की पहुंच स्थापित करने की संभावना बेहद कम है।[41]

इसके अलावा, सुलभ सार्वजनिक या सरकारी भवनों की कमी का मतलब है कि हिंसा की घटनाओं के बाद न्याय तक पहुंच

32 स्नाइडर और टेकेडा 2008

33 भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 2(ze)

34 विशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस्तीदार 2022

35 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 2011

36 राइजिंग फ्लेम 2020

37 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014

38 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014

39 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014

40 महापात्र एस और मोहंती एम 2004

41 राइजिंग फ्ललेम 2020

चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसमें हेल्पलाइन या वेबसाइटों की अनुपलब्धता, पुलिस स्टेशनों, अदालतों, चिकित्सा और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं में सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ विकलांग महिलाओं और लड़कियों और सामान्य महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए दुर्व्यवहार या हिंसा के मामलों से निपटने के लिए जागरूकता की कमी और कर्मियो की संवेदनशीलता शामिल हैं।

जैसा कि पहले के खंडों में बताया गया है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास सीमित आवाजाही के अधिक अवसर होते हैं।[42] जैसा कि नारीवादी विकलांगता विद्वानों ने उल्लेख किया है, विशेष रूप से विकलांग महिलाएं और लड़कियां लिंग और विकलांगता के दोहरे नुकसान से काफी प्रभावित होती हैं, खासकर तब, जब बुनियादी ढांचे के डिजाइन में कोई लिंग परिप्रेक्ष्य शामिल नही हो।[43] ऐसे मामलों में भी जहां बुनियादी ढांचा सुलभ है, नकारात्मक सामाजिक रूढ़िवादिता के साथ-साथ दुर्गम अंतिम मील कनेक्टिविटी के कारण विकलांग महिलाएं और लड़कियां अक्सर इसे प्राप्त करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने की स्थिति में नही होती हैं।

गतिशीलता और परिवहन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में बाधाओं के कारण, विकलांग महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से अपने घरों के भीतर और अक्सर उनके देखभाल करने वालों के हाथों दुर्व्यवहार और हिंसा के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं।[44] देखभाल पर निरंतर निर्भरता, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, और संस्थागतकरण का डर विकलांग महिलाओं और लड़कियों को हिंसा की रिपोर्ट करने से रोक सकता है, विशेष रूप से देखभाल करने वालों से, और उन्हें सुरक्षा सेवाओं की मांग करने से रोक सकता है।[45]

इसके अलावा, महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के पास हरे भरे स्थानों, पानी वाले स्थानों[46] और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, झीलों, सामुदायिक केंद्रों के साथ-साथ मनोरंजन स्थलों, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों, और अवकाश स्थलों तक पहुंच बहुत कम है, जिन्हें विकलांग और सामान्य महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सुलभता के लिए डिजाइन नही किया गया है।

घ. विचारणीय मुद्दे

भारतीय संदर्भ में शहरी विकास एजेंडा में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने में बाधा डालने वाले मुख्य मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं:

1. शहरी नीति और योजना में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के समावेशन के विचार की कमी:

जैसा कि परिलक्षित होता है शहरी स्थानों और सुविधाओं की योजना, डिजाइन और रखरखाव में महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों को काल्पनिक या इच्छित उपयोगकर्ताओं और शहरों और इसके सार्वजनिक स्थानों के निवासियों के रूप में 'योजनाबद्ध' नहीं किया जाता है। यह भागीदारी और जन-केंद्रित नियोजन प्रक्रियाओं की कमी के साथ-साथ अलग-अलग लिंग और विकलांगता के सटीक डेटा की अनुपस्थिति, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है।[47] नतीजतन, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों द्वारा शहरी स्थानों को कैसे देखा और उपयोग किया जाता है, इसकी समझ का एक अंतर्निहित अभाव है। इसने मनोसामाजिक विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मामलों में बदतर बना दिया गया है। भारत में अभिगम्यता की पहल अक्सर एक संकीर्ण फोकस को बनाए रखती है, विशेष रूप से शारीरिक, और काफी हद तक समझने योग्य, विकलांगता जैसे कि बिना क्रॉस-विकलांगता परिप्रेक्ष्य के लोकोमोटर विकलांगता।

2. शासन की चुनौतियां:

भारत के संविधान के तहत, किसी विशेष क्षेत्र के नियोजन, निर्मित स्थानों का नियमन और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे कार्य शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं पर विकसित होने चाहिए। रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में शहरी स्थानीय सरकारें

42 क्वान 2000

43 अदलखा 2022

44 यूएनएफपीए और वूमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल 2018

45 यूएनएफपीए और वूमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल 2018

46 हॉलैंड एफ 2021

47 विकलांग महिलाए इंडिया नेटवर्क 2019

संसाधनों और वित्तीय स्वायत्तता दोनों को बढ़ाने की क्षमता के मामले में दुनिया में सबसे कमजोर हैं।[48] इसके अलावा, अधिकांश भारतीय राज्यों में, राज्य स्तर पर एजेंसियां सामुदायिक भागीदारी कानूनों के बिना इन कार्यों को करना जारी रखती हैं। निर्वाचित नगरपालिका के बजाय केरल और पश्चिम बंगाल[49] जैसे राज्य इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। इसके अलावा, मौजूदा योजनाओं में भी, शहरी नियोजन और शासन में निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा, प्रक्रिया स्वयं न तो समावेशी है और न ही सहभागी है, जहां शहरी विकास एजेंडा तैयार करने और लागू करने के सभी चरणों में इनपुट को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

3. कार्यान्वयन अंतराल:

यह ऐसी चुनौतियां हैं, जो शहरी विकास एजेंडे में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से संबंधित मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन को रोकती हैं।

निर्मित पर्यावरण

बाधा मुक्त शहर बनाने के प्रयास में, आरपीडबल्यूडीए स्पष्ट रूप से[50] यह अनिवार्य बनाता है कि मौजूदा और नए सार्वजनिक भवनों को निर्धारित पहुंच मानकों का पालन करना चाहिए।[51] हालांकि, व्यवहार में, जागरूकता की कमी, विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता की कमी, जवाबदेही ढांचे की अनुपस्थिति और मजबूत भागीदारी योजना प्रक्रियाओं की कमी सहित कई कारकों के कारण इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की किसी भी स्पष्ट आवश्यकता के बिना, ये भवन पहुंच से बाहर हैं। इसी तरह, राज्य और स्थानीय स्तर की एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली खरीद प्रक्रिया किसी भी शहरी विकास एजेंडे के कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग है। अधिप्राप्ति नीतियां और निविदाएं आमतौर पर विकलांगता या लिंग संवेदनशील परिप्रेक्ष्य को शामिल करने में विफल रहती हैं।

परिवहन और आवाजाही

विकलांग व्यक्तियों को सुलभ परिवहन और आवाजाही प्रदान करने के लिए सरकारों को आरपीडबल्यूडीए के स्पष्ट जनादेश के बावजूद,[52] मल्टी-मोडल परिवहन की पहुंच, अंतिम-मील कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन के आसपास के बुनियादी ढांचे के निरंतर रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

भले ही राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी, 2014)[53] जन-केंद्रित परिवहन योजनाओं को बनाने और इसके आधार पर निर्णय लेने 3 की वकालत करती है, जिसमें महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सार्वभौमिक पहुंच पर जोर दिया गया है। लेकिन विशेष रूप से, शहरी परिवहन के लिए वर्तमान संस्थागत और कानूनी ढांचा, जो एकीकृत परिवहन योजना को सुविधाजनक बनाना मुश्किल बनाता है, अत: ऐसी चुनौतियों के कारण, इस नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

वर्तमान में, शहरी परिवहन योजनाएं कई स्तरों पर अलग-अलग, मौन एजेंसियों के बीच फैली हुई है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक खंडित संस्थागत ढांचा है,[54] और इससे शहरी परिवहन और आवाजाही की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग और समन्वित योजना में बाधा उत्पन्न होती है, और साथ ही यह सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के समग्र कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एनयूटीपी 2006 ने भारत के उन सभी शहरों में एकीकृत मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (यूएमटीए) की स्थापना की सिफारिश की थी, जहां 1 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। ताकि शहरी परिवहन कार्यक्रमों की समन्वित योजना और कार्यान्वयन की सुविधा मिल सके और एकीकृत शहरी परिवहन प्रणालियों का प्रबंधन किया जा सके। हालांकि, 53 में से केवल 15 शहरों[55] ने यूएमटीए की स्थापना की और यह देखा गया है कि यूएमटीए की स्थापना करने वाले शहरों में भी, यह सक्रिय कार्यात्मक भूमिका के बिना, काफी हद तक अप्रभावी रहा है।

48 अहलूवालिया 2011

49 टीईआरआई (टेरी) 2010

50 भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 44 और 45

51 सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश 2021

52 विशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस्तीदार 2022।

53 भारत, एनयूटीपी 2014

54 बेंदूर 2015

55 गिरिजे और गुप्ता 2020

शहरी परिवहन की योजनाओं में एक अन्य प्रमुख समस्या भूमि उपयोग की योजनाओं और गतिशीलता और परिवहन योजनाओं के बीच एकीकरण की कमी है। भूमि उपयोग और परिवहन योजना के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति 2017 की आवश्यकता है कि शहरों में मास्टर प्लानिंग अभ्यास के हिस्से के रूप में टीओडी नीति को अधिसूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों ने इसे टुकड़ों में अपनाया है। ऊपर उल्लिखित सभी समस्याएं भारतीय शहरों में शहरी परिवहन और गतिशीलता के लिए सार्वभौमिक पहुंच हासिल करने में एक गंभीर बाधा उत्पन्न करती हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तक पहुंच के संदर्भ में भी, आरपीडब्ल्यूडीए स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार द्वारा सभी सामग्री, ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।[56] इसके अलावा, आरपीडबल्यूडीए के तहत निर्धारित[57] एक्सेसिबिलिटी मानकों के बावजूद, भारत में कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप इसका पालन नहीं कर रहे हैं।[58]

> 2012 के एक अध्ययन[59] में 7,800 सरकारी वेबसाइटों का परीक्षण किया गया, और यह पाया गया कि 1,985 खुलने में विफल रहे, जबकि शेष 5,815 वेबसाइटों में से अधिकांश तक पहुंच बनाने में बाधाएं उत्पन्न हुई थीं।

हालांकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) नियम 60 के लिए सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों को[60] एक्सेसिबिलिटी मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों में केवल यह आवश्यक है कि सरकारी वेबसाइटों को उनके दायरे में निजी वेबसाइटों को शामिल किए बिना सुलभ बनाया जाए। इसके कारण आवेदन में अस्पष्टता और पहुंच की निरंतर कमी दिखाई देती है।[61]

भारत में, यह देखा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों[62] के अनुसार, आधे से अधिक पुरुषों (57 प्रतिशत) की तुलना में, तीन में से केवल एक महिला (33 प्रतिशत) ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। 2 शहरी परिवेश में, पुरुषों के 72.5 प्रतिशत की तुलना में केवल 51.8 प्रतिशत महिलाओं ने ही इंटरनेट का उपयोग किया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि विकलांग व्यक्ति विशेष रूप से विकलांग महिलाओं में मोबाइल फोन, विशेष रूप से स्मार्ट फोन,[63] और मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना बेहद कम है। ऐसा डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी, सामर्थ्य की कमी, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, मोबाइल फोन के उपयोग से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं,[64] और साइबर यौन उत्पीड़न के खतरे के कारण है।[65]

डिजिटल पहुंच की कमी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से यह विकलांग महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रहा है, जो पहले से ही डिजिटल लिंग अंतर से प्रभावित हैं। यह कोविड-19 महामारी के दौरान और अधिक महसूस किया गया है, जहां वेबसाइटों और मोबाइल ऐप तक पहुंच पर आवश्यक चीजों की पहुंच आकस्मिक थी।[66] पूरे भारत में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वाकांक्षी जनादेश के बावजूद, उन्हें अधिक डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की दिशा में ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर सीमित तौर पर विचार किया गया है। 22 स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के विश्लेषण के आधार पर नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) द्वारा किए गए एक अध्ययन में,[67] यह पाया गया कि स्मार्ट सिटी के मुख्य बुनियादी ढांचे के तत्वों में पहुंच संबंधी विचार और डिजिटल समावेशन की भूमि का शामिल नहीं थी। और साथ ही इसमें विकलांगों की उपेक्षा भी की

56 भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 42

57 जीआईजीडब्ल्यू 2009

58 सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी 2012

59 सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी 2012

60 नियम 15, आरपीडब्ल्यूडी नियम

61 भारत, भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश, 2009

62 पीआरएस 2020

63 जैन. सी.ए. और शनहान. एम 2020

64 ओईसीडी 2018

65 जैन. सी.ए. और शनहान. एम 2020

66 राइजिंग फ्लेम एंड साइट सेवर्स 2020

67 एनसीईपीडीपी और एफआईसीसीआई 2021

गई। डिजिटल समावेशन नीतियों और कार्यक्रमों के लिए एक लिंग-संवेदनशील और विकलांगता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग लड़कियों और महिलाओं को डिजिटल पहुंच से बाहर न रखा जाए।

महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है। डिजिटल सेवाओं की अधिकता तक पहुंच की कमी महिलाओं और लड़कियों को विकलांग और उनके परिवारों या देखभाल करने वालों पर निर्भर बनाती है, विशेष रूप से मानवीय संकट के समय में जैसा कि कोविड-19 महामारी में देखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, आरपीडबल्यूडीए को सरकार से उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, जिसमें एक व्यापक बीमा योजना भी शामिल है जो किसी अन्य वैधानिक या सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत नहीं आती है।[68] विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए विशिष्ट, सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं में छात्रवृत्ति योजनाएं (जहां हर साल कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50 प्रतिशत विकलांग लड़कियों को आवंटित किया जाता है), कुछ ऋण आधारित योजनाओं[69] के तहत विकलांग महिलाओं को उपलब्ध ब्याज पर छूट शामिल है।। इसके साथ ही इसमें विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (SIPDA)[70] (जैसे कि बाधा मुक्त शहरी स्थानों के लिए सुगम भारत अभियान), विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (जहां प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल सेवन का 30 प्रतिशत विकलांग महिलाओं के लिए निर्धारित है) और साथ ही निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। कुछ योजनाओं (जैसे राष्ट्रीय न्यास की निर्माया बीमा योजना) के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों को सस्ता स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।[71]

इसके बावजूद, भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त और खंडित बनी हुई है, जिनमें से अधिकांश ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं।[72] इसमें कुछ मुद्दों में प्रक्रिया की दुर्गमता,[73] सामाजिक सुरक्षा योजना की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट मानक की कमी,[74] क्षमता की कमी और स्थानीय कार्यान्वयन स्तरों पर कमजोर डेटा प्रबंधन प्रणाली और योजनाओं के बारे में ज्ञान की कमी शामिल है।[75]

4. समन्वय और मौन एजेंसियो की कमी

विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी भी है, चाहे वह एक ही स्तर पर हो या विभिन्न स्तरों पर और वे मौन रह कर काम करना जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) बेंगलुरु, कर्नाटक में सार्वजनिक बसें चलाता है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) (बेंगलुरु का शहरी स्थानीय निकाय) शहर में बस शेल्टर बनाने और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। बस शेल्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बस परिवहन सुलभ रहे क्योंकि कर्ब-साइड सुविधाएं, रैंप और रेलिंग बसों में प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान करती हैं। सुलभ बस ट्रांज़िट सुविधाओं के लिए, बीबीएमपी और बीएमटीसी के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसकी अक्सर कमी देखी जाती है।[76]

68 भारत, आरपीडब्ल्यूडी सेक्शन 24

69 एनएचएफडीसी 2016

70 एनएचएफडीसी 2016

71 निरमया 2008

72 **वैपलिंग**, शजोएड्ट और सिबुन 2021

73 **वैपलिंग**, शजोएड्ट और सिबुन 2021

74 **वैपलिंग**, शजोएड्ट और सिबुन 2021

75 **वैपलिंग**, शजोएड्ट और सिबुन 2021

76 विशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस्तीदार 2022

5. संवेदीकरण, जागरूकता और क्षमता-निर्माण की कमी:

आरपीडब्ल्यूडीए स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार जागरूकता अभियान, संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगी और विकलांग व्यक्तियों के बेहतर कार्यान्वयन और सुरक्षा के लिए मानव संसाधन विकसित करेगी।[77] इसके बावजूद, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं की आवश्यकताओं को समझने में संवेदनशीलता, जागरूकता और तकनीकी क्षमता की गंभीर कमी है। और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह की आवश्यकताओं को शहरी विकास एजेंडे में कैसे शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ जमीनी स्तर के कार्यान्वयन में शामिल निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच भी उपर लिखी हुई दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

[77] **भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 39 और 47**

VI. लिंग और विकलांगता समावेशी विकास में उभरते क्षेत्र

हितधारकों के परामर्श से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, यह बात सामने निकल कर आई है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों का मुकाबला करने के लिए शहरी रणनीतियों में लिंग और विकलांगता समावेशन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (सेंडाई फ्रेमवर्क) "बेहतर निर्माण" के बारे में विस्तार से बताता है कि, विशेष रूप से "विकलांग महिलाओं और व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से नेतृत्व करने और लैंगिक न्यायसंगत और सार्वभौमिक रूप से सुलभ प्रतिक्रिया, वसूली, पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना" और पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानना ज़रुरी है। इसमें स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों और उनके संगठनों का प्रमुख हितधारकों के रूप में उल्लेख किया गया है, जो आपदा जोखिम के आकलन में महत्वपूर्ण हैं और यह सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने में भी महत्वपूर्ण हैं।

वाली घटनाएं शामिल हैं, जिसमें लिंग आधारित हिंसा, आवश्यक सेवाओं से इनकार करना और न्याय तक पहुंच बनाने में आने वाली बाधाएं शामिल हैं। जबकि महिलाओं और लड़कियों, विकलांग और सामान्य लोग, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अद्वितीय बाधाओं का सामना करते हैं। यह स्थिति विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए विकट है। उदाहरण के लिए, विकलांग महिलाओं में शारीरिक बाधाओं, पूर्व चेतावनी सूचना की अनुपलब्धता और परिवार के सदस्यों और समुदाय[78] से समर्थन की कमी के कारण आपदाओं से भागने की सीमित क्षमताएं हो सकती हैं। नगरपालिका शासन के विभिन्न स्तरों पर लिंग और विकलांगता के दृष्टिकोण से आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को विकसित करना आवश्यक है

> "विकलांग पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के रूप में, एक क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह कि देखा जाए कि नीतियों में विकलांगता के पहलू को किस हद तक कवर किया गया है। दूसरा, इंजीनियरों और वास्तुकारों का वर्तमान पाठ्यक्रम किस हद तक सभी के लिए पहुंच और सार्वभौमिक डिजाइन को कवर करता है। इस विशेष उद्देश्य के लिए कितने संसाधन समर्पित किए गए हैं और क्या सार्वभौमिक अभिगम्यता डिजाइन पर विशिष्ट विषयों को पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियो का ध्यान इस पर गया है, ऐसे कई और प्रश्न हैं जिन्हें हमें लगातार पूछते रहने की आवश्यकता है।"
>
> -डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गनाइज़ेशन (विकलांग जन संगठन) के प्रतिनिधि [21 मार्च, 2022 को विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित फोकस ग्रुप डिस्कशन]

[78] वूमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल कमेंट्स 2017

VII. सिफारिशें

राष्ट्रीय स्तर पर

1. नारीवादी और लिंग परिवर्तनकारी शहरी नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी, नीति और नियामक सुधारों के माध्यम से उपकरणों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने सहित सक्षम शहरी नियोजन दृष्टिकोण बनाना। यह नियोजन उपकरण के रूप में नारीवादी और लिंग परिवर्तनकारी परिप्रेक्ष्य को शामिल करके किया जा सकता है।[79] स्पेन में देखा गया था कि कैटलोनियन पड़ोस विकास कानून के माध्यम से, योजना और शहरी विकास कानून में लिंग परिप्रेक्ष्य स्थापित हुआ। यूरोपीय आयोग द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त, इस कानून ने "शहरी स्थान और सुविधाओं के उपयोग में लिंग समानता" को शहरी पुनर्जनन परियोजनाओं के लिए फंडिंग की सहायता की आवश्यकता के रूप में निर्धारित किया, जिसका उद्देश्य पड़ोस के शहरी क्षेत्रों और कस्बों में सुधार करना था।
2. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मौजूदा कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों में संशोधन करना या पहुंच संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें विशेष रूप से विकसित करना। कोविड-19 जैसी मानवीय आपात स्थितियों के साथ-साथ लॉकडाउन या अन्य गतिशीलता प्रतिबंधों के मामले में सेवा वितरण को अनुकूलित करना।
3. शहरी नियोजन और शासन में निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, विशेष रूप से लड़कियां, बच्चे और विकलांग महिलाएं जिसमें 15वें वित्त आयोग के हिस्से के रूप में स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित मुद्दों और निधियों की प्राथमिकता में भागीदारी शामिल है।
4. यूएनसीआरपीडी के उल्लंघन में कानून में संशोधन और/या कानून को निरस्त करना और यह सुनिश्चित करना कि मनोसामाजिक या बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और लड़कियों पर जोर देने के साथ, कानूनी क्षमता, कानून के समक्ष समान मान्यता, भेदभाव से मुक्ति, अनैच्छिक हिरासत और जबरन उपचार सहित हिंसा से सुरक्षा, और निर्णय लेने में सहायता करना।
5. महिलाओं और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ शासन के विभिन्न स्तरों पर लिंग और विकलांगता संवेदनशील आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) रणनीतियों का विकास और डिजाइन और सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप समावेशी विकलांगता संवेदनशील आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।
6. विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन और गतिशीलता को आसान बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों में संशोधन और उपयुक्त नीतियों, मानकों और दिशानिर्देशों को विकसित करना, जैसे मोटर वाहन वाहनों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने के उपाय, लोगों को बीच सार्वभौमिक रूप से सुलभ सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखना।
7. आरपीडब्ल्यूडीए के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नीति सलाहकार बोर्डों और प्रवर्तन निकायों (जैसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विकलांगता नीति सलाहकार बोर्ड और विकलांगता आयुक्त) को संगठित करना। जैसा कि आरपीडब्ल्यूडीए के तहत अनिवार्य है, विशेष रूप से, इन निकायों में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।[80] इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडीए के तहत विकलांगता नीति सलाहकार बोर्डों को विकलांगता से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान केंद्र और राज्य स्तर पर विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।[81] इसके अलावा, शहरी विकास में शामिल स्थानीय स्तर सहित सरकारों के विभिन्न स्तरों पर निकायों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए प्रभावी और कुशल प्रणाली भी होनी चाहिए। इस तरह की प्रणालियों को सरकारी एजेंसियो, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र के निकायों, नागरिक समाज संगठनों

[79] मार्टिनेज जेड और सिओकोलेटो ए 2009

[80] भारत, आरपीडब्ल्ययू डीए, धारा 60 और 66

[81] भारत, आरपीडब्ल्ययू डीए, धारा 65 और 71

द्वारा क्षमता निर्माण के साथ-साथ लिंग और विकलांगता समावेशी शहरी विकास एजेंडा की अवधारणा, डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए परामर्श को सक्षम बनाना चाहिए

8. यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और विकलांगता के लिए राज्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और विकलांग लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच करें, इसके लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन दिए जाएं और स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की क्षमता के साथ सशक्त किया जाए।
9. यह सुनिश्चित करना कि विकलांग महिलाओं और मनोसामाजिक या बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय विकलांग आयोग और राज्य विकलांगता आयोगों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के पास पर्याप्त संसाधन हों और महिलाओं और लड़कियों सहित विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की क्षमता हो।

राज्य स्तर पर

1. भूमि के अधिकार में वृद्धि का महिलाओं की स्वतंत्रता और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी भूमि प्रबंधन प्रयासों में महिलाओं के लिए शीर्ष विकल्पों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने वाले शहरी भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. 74वें संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की परिकल्पना की गई है, जो मास्टर प्लान या शहरी विकास योजना तैयार करने जैसे नियोजन कार्य करते हैं।
3. आरपीडब्ल्यूडीए के तहत अधिसूचित सुगम्यता मानकों को सुनिश्चित करना, जैसे कि, 2021 के सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और सार्वभौमिक पहुंच के लिए मानक, सार्वजनिक परिवहन के लिए बस बॉडी कोड, और भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश, राज्य और नगरपालिका स्तर पर प्रासंगिक कानूनी ढांचे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में एकीकृत की जाए।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन के तंत्र की स्थापना करना कि नगरपालिका स्तर पर नियमों और विनियमों (जैसे भवन उप-नियमों) को राष्ट्रीय पहुंच मानकों में बदलाव के अनुरूप बदलाव किया जाए, जिसमें टीओडी नीति में उल्लिखित विकलांग व्यक्ति, महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
5. एनयूटीपी 2014 में उल्लिखित एकीकृत परिवहन योजना के लिए सभी शहरी एजेंसियो और हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक पूर्णकालिक पेशेवर निकाय के रूप में, पर्याप्त कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ कानून द्वारा समर्थित सभी 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में समर्पित यूएमटीए की स्थापना करना।
6. टीओडी नीति में उल्लिखित मास्टर प्लान अभ्यास के माध्यम से शहरी नियोजन अभ्यास में परिवहन योजना के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा योजना कानूनों और नीतियों में संशोधन करके परिवहन और भूमि उपयोग नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करना।
7. सार्वजनिक खरीद कानूनों में संशोधन करना और लिंग और विकलांगता के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए खरीद नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना, जैसे सार्वभौमिक पहुंच को प्रमुख मानदंड के रूप में शामिल करना, विशेष रूप से शहरी बुनियादी ढांचे और सेवा प्रावधान के संदर्भ में, जिसमें निर्मित पर्यावरण, परिवहन और आवाजाही, आईसीटी और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में समावेशी खरीद प्रथाओं को बढ़ावा देना।
8. एजेंसियां (जैसे योजना एजेंसियां, विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय) द्वारा शहरी विकास एजेंडा की स्थापना, कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल प्रक्रियाएं पारदर्शी, लिंग और अक्षमता केंद्रित, समावेशी और भागीदारीपूर्ण होनी चाहिए। विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, युवाओं और विकलांग व्यक्तियों से विभिन्न, सुरक्षित और सुलभ तरीकों से भागीदारी और इनपुट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

नगर निगम स्तर पर

1. भारत में शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं को शहरी नियोजन और सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा, प्रतिनिधि वार्ड समितियों को अपने संबंधित वार्डों की योजना बनाने और महिलाओं, बच्चों, विकलांग युवाओं, विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह की समितियों को अपनी विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से नगर पालिका को अपनी आवश्यकताओं पर विचार करने और संवाद करने के लिए और अधिक संगठित किया जाना चाहिए।
2. शहरों में लड़कियों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्कों, झीलों के साथ-साथ मनोरंजन स्थलों, सांस्कृतिक

और विरासत स्थलों और अवकाश स्थलों जैसे हरे और पानी वाले स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करना। महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों को ऐसे स्थानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्राम स्थलों की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाएं अनुकूल समय और प्रवेश प्रतिबंधों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे स्थान सुरक्षित हों, महिलाओं, लड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ हों।

3. शहरों में सार्वजनिक वॉश बुनियादी ढांचे को डिजाइन करना और उपलब्ध कराना और साथ ही साथ वॉश कार्यक्रमों को लागू करना, जो लिंग और विकलांगता समावेशी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ हो और विशेष रूप से विकलांग लड़कियों और महिलाओं की जरूरतों को पूरा करती हों। लोगों द्वारा ऐसी सुविधाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यक है कि लिंग-तटस्थ स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, मासिक धर्म के स्वास्थ्य उत्पादों का प्रावधान किया जाए और बच्चों के अनुकूल उनका डिजाइन तैयार की जाएं।

केस अध्ययन

किलिकिली-भारतीय शहरों में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी खेलने के स्थान बनाना

किलिकिली, एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जो सभी बच्चों के लिए समावेशी सार्वजनिक स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था और इस तरह यह एक ऐसे समाज को बनाने में मदद करता है जहां विकलांगता भेदभाव और बहिष्कार का कारण नहीं बनती है। संगठन सार्वजनिक स्थान के संभावित उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी भागीदारी प्रक्रियाओं के लिए अद्वितीय है, जिसमें बच्चों के परामर्श को खेल स्थलों पर समावेशी बनाना उनके काम का केंद्र बिंदु है। उन्होंने बीबीएमपी जैसी नगरपालिका एजेंसियो के साथ भागीदारी की है और 2021 तक आठ समावेशी सार्वजनिक खेल स्थलों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

वे पार्कों को समावेशी बनाने के लिए काम करते हैं और सुरक्षित झूलों, सुलभ बास्केटबॉल पोल, व्हीलचेयर सुलभ मीरा-गो-राउंड के साथ-साथ ऑटिज्म जैसी न्यूरोडिवर्जेंट स्थितियों वाले बच्चों के लिए शांत क्षेत्र वाले बहु-संवेदी पार्कों को डिजाइन करते हैं। वे एक्सेस ऑडिट और एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस, समावेशी प्ले स्पेस डिजाइन करने, विकलांग या सामान्य बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन कार्यक्रम डिजाइन करने और बच्चों की भागीदारी बढ़ाने जैसी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

सामान्य सिफारिशें

1. तकनीकी

1. विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं और लड़कियों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम करने के लिए लिंग-परिवर्तनकारी और आयु-प्रतिक्रियात्मक योजना प्रक्रियाओं को अपनाना। योजना और डिजाइन प्रक्रिया को समाविष्ट करने के लिए नियोजन उपकरण जैसे कि लिंग विश्लेषण, सुरक्षा ऑडिट, अन्वेषिक सैर, आदि को शामिल करना।
2. सभी शहरी विकास परियोजनाओं और सेवा वितरण के लिए डिजाइन के चरणों में सार्वभौमिक डिजाइन दृष्टिकोण को प्रगतिशील रूप से अपनाना। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए 2021 के सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और मानकों को प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाना। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सार्वभौमिक डिजाइन मानदंड को शामिल करने से बाद रेट्रोफिट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है,[82] और इसमें केवल 0-1 प्रतिशत अतिरिक्त लागत (यदि कोई हो) लगती है। अक्सर अभिगम्यता के लिए किसी भवन को फिर से डिज़ाइन करने के लिए किसी अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मौजूदा योजना का पुनर्वव्स्थापन होता है।[83]
3. लक्षित शहरी नीति निर्णयो को बेहतर ढंग से सूचित करने और कार्यान्ववित करने के लिए लिंग और विकलांगता पर सटीक और विश्वसनीय अलग-अलग डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए सिस्टम विकसित करना।
4. डिजिटल डिवाइड और डिजिटल जागरूकता और साक्षरता के अंतर को पाटने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का डिजाइन और निर्माण करना, जिसका सामना महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और विकलांग बच्चों को करना पड़ता है। यह सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाएगा जो एक शहरी वातावरण को प्रदान करनी चाहिए जैसे कि सुरक्षित आवाजाही, अन्य लाभों के अलावा, सटीक जानकारी तक पहुंच और शहरी शासन प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक भागीदारी।
5. समावेशी शहरी विकास में आने वाली बाधाओं को समझने और दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी पार्टियों के बीच साझेदारी में विभिन्न समावेशी और सुलभता पहलों के नियमित लिंग और अक्षमता ऑडिट आयोजित करना, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ अंतर-संबंधों के परिप्रेक्ष्य से इसकी समीक्षा और उपाय करना। इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के लिए बीमा पॉलिसियों को डिजाइन और जारी करने के साथ-साथ ऐसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक जागरूकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए।
6. अस्पतालों और आश्रय गृहों जैसे संस्थानों में विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाए देखने को मिलती हैं। स्टाफ सदस्यों को सुग्राही बनाने के अलावा ऐसे संस्थानो के लिए समय-समय पर जांच के साथ उन पर पैनी निगरानी और नियामक प्राधिकरण आवश्यक है।

2. सामाजिक

1. योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, रखरखाव और शहरी विकास एजेंडा की निगरानी में शामिल सरकारी और निजी खिलाड़ियों के सभी स्तरों पर विकलांगता और लिंग परिवर्तनकारी प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण करना। भारत भर के शहरों और कस्बों में सेवा वितरण में शामिल नगरपालिका के स्तर पर कर्मचारियों को लिंग और विकलांगता के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है।
2. विभिन्न सरकारी स्तरों पर नियमित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, स्कूलों और विश्वविद्यालय स्तरों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महिलाओं के अध्ययन और विकलांगता अध्ययन को अनिवार्य किया जाएगा।
3. डीपीओ, नारीवादी और महिला अधिकार संगठनों, और महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए काम करने वाले संगठनों की बड़ी भूमि का और भागीदारी, ऐसे व्यक्तियों के बीच नेटवर्क के गठन की सुविधा प्रदान करके, सटीक जानकारी प्रदान करना। और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में मदद करना, और प्रौद्योगिकी के उपयोग और सरकारी लाभों तक पहुंचने में उनका समर्थन करना। डीपीओ विकलांग व्यक्तियों के समुदायों के साथ अपने मजबूत नेटवर्क के कारण

82 सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश 2021

83 स्नाइडर और टेकेडा 2008

विकलांगता-पृथक डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसमें कई हितधारक हैं, जैसे सरकार के विभिन्न स्तर, डीपीओ, संगठन, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कानूनों, नीतियों और योजनाओं के साथ निजी क्षेत्र, आदि, जो एक साथ शहरी विकास को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वास्तव में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करते हैं। नतीजतन, इस तरह का कोई भी समावेश केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब बहु-क्षेत्रीय प्रयासों का अभिसरण हो और स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और योजना क्षमताओं के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाएं।[84]

केस अध्ययन

सियोल का 'वुमन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट'

सियोल का 'वुमन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट' शहरी पर्यावरण के तीन मुद्दों-सुविधा, सुरक्षा और वैमनस्य को बेहतर करने और महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना को वर्ष 2010 में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2007 में, सियोल के नागरिकों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 77.4 प्रतिशत असुविधाएं जो महिलाएं अनुभव करती हैं, वे उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हैं जैसे-सार्वजनिक विश्राम कक्ष, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग, बच्चों की देखभाल की सुविधा, रास्तों पर चलना आदि, और 67.3 प्रतिशत महिलाएं शहर में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं या शहरी जीवन से निराश हैं।

इस परियोजना ने महिलाओं के दैनिक जीवन से निकटता से संबंधित पांच क्षेत्रों को लक्षित करके महिलाओं को पर्याप्त लाभ पहुचाने का काम किया जैसे देखभाल, काम, समृद्धि, सुविधा और सुरक्षा, रेस्टरूम की सुविधा को बढ़ाना, परिवहन और सड़क सुविधाओं में सुधार के लिए निर्देशित हस्तक्षेप आदि। चार साल की योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 90 मुख्य कार्यक्रम शामिल थे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार के हर विभाग ने महिलाओं के दृष्टिकोण को उन नीतियों में शामिल करने का प्रयास किया, जिनसे वे निपट रहे हैं। इस परियोजना में नागरिकों, महिलाओं के समूहों, नगरपालिका सरकार के संबंधित अधिकारियों और महिलाओं के मुद्दों, कल्याण, सड़क, परिवहन, आवास, वास्तुकला और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित कई तरह के हितधारक शामिल थे।

84 **नीति आयोग 2021**

3. आर्थिक

1. महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के लिए बाजार से जुड़ाव और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन और आवधिक समीक्षा करना। इसमें शहरी क्षेत्रों (जैसे स्व-रोजगार महिला संघ या सेवा और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामूहिक कार्रवाई या स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना शामिल है। कौशल विकास, एक मजबूत नेटवर्क और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, ऐसे समूहों को क्रेडिट लाइन, स्वास्थ्य देखभाल, चाइल्डकेयर, बीमा, आवास सहायता,[85] सह-शिक्षण और जागरूकता जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। यह देखते हुए कि शहरों में आमतौर पर सामाजिक एकता कम होती है, ऐसे समूहों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।[86] इसके अलावा, व्यापार उद्यमों के लिए ऋण, लघु ऋण या अनुदान प्रदान करने, सहकारी समितियों की स्थापना, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विशिष्ट पहल होनी चाहिए।[87]
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट, RPWDA सरकार से विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए रोजगार की सुविधा के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने सहित योजनाओं को तैयार करने का आग्रह करता है।[88] नतीजतन, व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल सार्वजनिक संस्थानों का समर्थन करके और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित कौशल विकास योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, हितधारकों के बीच ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने, सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और विशेष रूप से स्थानीय कार्यान्वयन स्तरों पर योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण और बेहतर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली बनाना। इसके अलावा, RPWDA के तहत निर्धारित सार्वजनिक रोजगार प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए।
3. पट्टे पर देने की जगह, ऋण और अनुदान, लाइसेंस आदि पर सब्सिडी देकर रेहड़ी-पटरी वालों, विशेषकर महिलाओं और अन्य अनौपचारिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करना। शहरी सुविधाओं और अवसरों, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि "आंखें सड़क पर लगी रहे"[89] की अवधारणा का पालन करते हुए सड़कों का लगातार उपयोग किया जाए।

4. गतिशीलता

1. गतिशीलता और परिवहन योजनाओं में उन विभिन्न स्थानों पर विचार करना चाहिए, जहां महिलाओं को पहुंच की आवश्यकता होती है (पहुंच और डिजाइन की पारंपरिक धारणाओं के अलावा); न केवल मुख्य शहरी क्षेत्रों में बल्कि पेरी-शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना।[90] इस तरह की योजना प्रभावित लोगों, विशेषकर महिलाओं और विकलांगों और सामान्य लड़कियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए; उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए गतिशीलता और परिवहन मार्गों की योजना बनाई जानी चाहिए जिन्हें घरेलू संसाधनों, वॉश सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल, अनौपचारिक कार्यस्थलों और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बच्चों के लिए सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करनी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की योजना को अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए; और यह सुलभ, अच्छी तरह से जुड़ी और वहनीय होनी चाहिए।
2. भूमि उपयोग योजना को परिवहन योजना को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए ताकि उससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी क्षेत्र और इसकी परिधि जुड़े रहें और शिक्षा, रोजगार और अन्य संसाधनों जैसे सभी प्रकार के अवसरों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके। परिवहन आर्थिक क्षेत्रों के विकास को सक्षम बनाता है।
3. शहरों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बच्चों और युवाओं को मुफ्त या अत्यधिक किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए नीतियां विकसित करना।
4. शहरी नियोजन जन-केंद्रित होना चाहिए, लड़कियों और महिलाओं की गतिशीलता और व्हीलचेयर की पहुंच और सुरक्षा को सक्षम करने के लिए सुलभ सड़कों और पैदल चलने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन नीतियों

85 पॉज़र्नी 2016

86 सिंह, रविशंकर और पिल्लै 2020

87 सिंह, रविशंकर और पिल्लै 2020

88 भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 19

89 जैकब 1992

90 संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (यूएन हैबिटेट) 2020

पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सुरक्षा, अधिक समावेश, अंतिम-मील कनेक्टिविटी और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करती हैं।[91] मोबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को गैर-मोटर चालित परिवहन, मुफ्त या कम लागत वाले सार्वजनिक परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों में शौचालय आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कनेक्टिविटी और आवृत्ति को प्राथमिकता देता है।

केस अध्ययन

महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन: दिल्ली सरकार की पहल

महिलाओं और लड़कियों के लिए लिंग आधारित वेतन के अंतर और आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, दिल्ली सरकार ने 2019 में शहर में सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बस परिवहन को मुक्त बनाने के लिए पिंक स्लिप अभियान शुरू किया। यह देखते हुए कि शहर के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 11 प्रतिशत है और दैनिक तौर पर दिल्ली मेट्रो और बसों में केवल 30 प्रतिशत महिलाएं सफर करती हैं, दिल्ली सरकार ने शहर में महिलाओं की आवाजाही को प्रोत्साहित किया। महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच में सुधार करके, इसने महिलाओं और शहरी स्थानों को सुरक्षित बना दिया, यह मानते हुए कि सामूहिक पारगमन महिलाओं को सुरक्षा की भावना देता है, क्योंकि एक साथ यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक होती है।[92] इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से अब महिलाएं अपनी बचत को पोषण या व्यक्तिगत बेहतरी में लगा सकती हैं। इस पहल से महिला सवारियों को बढ़ावा मिला है, जिससे शहर की कामकाजी महिलाओं को काफी फायदा हुआ है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अपनी बसों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती हेतु नियमों में ढील के माध्यम[93] से सार्वजनिक परिवहन में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें महिला आवेदकों के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 159 सेमी से घटाकर 153 सेंमी करना और "अनुभव मानदंड" को एक महीने तक कम करना शामिल है। एक और पहल में, दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए शहर में नए इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 4,261 नए परमिटों में से 1,406 (33 प्रतिशत) आरक्षित किए हैं

91 भारत, आरपीडब्ल्यूडीए, धारा 41

92 केजरीवाल ए, 2019

93 गोस्वामी एस 2022

संदर्भ

- अदलखा 2022, "Slow Progress for Women with Disabilities in India", ("स्लो प्रोग्रेस फॉर वुमन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया") 121 (834) करंट हिस्ट्री 129-134।
- अग्रवाल और पांडा 2007. “Toward Freedom from Domestic Violence: The Neglected Obvious.” ("टूवर्ड फ्रीडम फ्रॉम डोमेस्टिक वाइलेंस: नेगलेक्टिड ऑबवियस") जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 8 (3), 359-388. Doi: 10.1080/14649880701462171.
- अहलूवालिया 2011, "Report on Indian Urban Infrastructure and Services" ("रिपोर्ट ऑन इडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एडं सर्विसेज"), एचपीईसी, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- बैंदूर 2015, "Urban Transport in India: Challenges and Recommendations" ("अर्बन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया: चैलेंजेस एंड रिकमंडेशन्स"), आईआईएचएस।
- जनगणना 2011. प्राथमिक जनगणना, भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 2016, "Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act" ("विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना")। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत।
- फेनस्टीन और सेवरन 2005. “Gender and Planning: A Reader” ("जेंडर एंड प्लानिंग: ए रीडर"), रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस।
- गिरिजे और गुप्ता 2020, "Urban Transport Governance Practice and Challenges in an Emerging Economy - Case Study of India" ("अर्बन ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड चैलेंजेस इन ए इमर्जिंग इकोनॉमी- केस स्टडी ऑफ इंडिया"), 48 ट्रांसपोर्ट रिसर्च प्रोसीडिया।
- गोस्वामी एस 2022, “Delhi ups efforts to boost female staff in public transport workforce” ("डेल्ही अप्स एफर्ट टू बूस्ट फीमेल स्टाफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कफोर्स"), नई दिल्ली : हिंदुस्तान टाइम्स, 7 मार्च 2022, 9 अप्रैल 2022 को उपलब्ध, नीचे इसका लिंक दिया गया है
- https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/delhi-ups-efforts-to-boost-female-staff-in-public-transportworkforce-101646591711475.html
- जीएसएमए 2020, "The Digital Exclusion of Women with Disabilities" ("द डिजिटल एक्सक्ल्यूज़न ऑफ वुमन विद डिसेबिलिटी") जीएसएमए।
- हॉलैंड एफ 2021, "आउट ऑफ बाउंड्स: इक्विटी इन एक्सेस टू अर्बन नेचर": ग्राउंडवर्क यूके।
- ह्यूमन राइट्स वॉच 2014, “ Treated Worse than Animals- Abuses against Women and Girls with Psychosocial or Intellectual Disabilities in Institutions in India” ("ट्रीटिड वर्स देन एनिमल - एब्यूसिस अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स विद साइकोलॉजिकल ऑर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इन इंस्टिट्यूशन्स इन इंडिया: ह्यूमन राइट्स वॉच।
- भारत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 14 दिसंबर 2016
- जैकब्स 1992. “The Death and Life of Great American Cities” ("द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज"), विंटेज बुक्स।
- केजरीवाल ए 2019, “Free transport: Delhi government’s landmark move to empower women, give them greater claim to public spaces” New Delhi: Times of India, 3 नवंबर 2019, 9 अप्रैल, 2022 को एक्सेस किया गया, Link:- https://timesofindia पर उपलब्ध है। indiatimes.com/blogs/for-the-People/free-transport-delhi-governments-landmark-move-to-empower-women-give-them-greater-claimto-public-spaces/
- खोसला 2009. " भारत के शहरी नवीकरण मिशन में जेंडर संबंधी चिंताओं को संबोधित करना: ", नई दिल्ली: यूएनडीपी।
- कूनन एस 2019, “Sanitation Interventions in India: Gender Myopia and Implications for Gender Equality”(सेनिटेशन इंटरवेंशन इन इंडिया: जेंडर मायोपिया एंड इंप्लिकेशन फॉर जेंडर इक्वेलिटी")। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज.;26(1-2):40-58.
- क्वान 2000, "Gender Differences in spacetime constraints" (जेंडर डिफरेंस इन स्पपेस-टाइम कंस्ट्रेट्स), 32.2 एरिया।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 2021, "भारत में सार्वभौमिक पहुँच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक" भारत सरकार।
- कार्मिक मंत्रालय 2009, "भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश" लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2008, "निरम्या स्वास्थ्य बीमा योजना", भारत सरकार।
- शहरी विकास मंत्रालय 2014, "राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014", भारत सरकार।
- महापात्र एस और मोहंती एम 2004, “Abuse and Activity Limitation: A Study on Domestic Violence against Disabled Women in Orissa, India” (अब्यूज़ एडं एक्टिविटि लिमिटेशन: ए स्टडी ऑन डोमेस्टिक वाइलेंस अगेंस्ट डिसेबल्ड वुमन इन ओरिसा, इंडिया")
- मुक्सी मार्टिनेज, जेड और सिओकोलेटो, ए 2009, Catalonian Neighbourhood Development Law: The Gender Perspective as a Planning Tool" (1331-1338) ("कैटलोनियन नेबरहुड डेवलपमेंट लॉ: द जेंडर पर्सपेक्टिव एज़ ए प्लानिंग टूल" (1331-1338), शहरीवाद (अर्बेनिज़्म) पर अंतर्राष्ट्रीय मंच का चौथा सम्मेलन।
- नरसिम्हन, शर्मा और कौशल 2012, "Accessibility of Government Websites in India: A Report"(एक्सेबिलिटी ऑफ गवर्मेंट वेबसाइट इन इंडिया: ए रिपोर्ट") . सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी इंडिया और हंस फाउंडेशन।
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम 2016, "दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना"। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत।
- एनसीपीईडीपी और एफआईसीसीआई 2021, "Structural Framework for Accessible Urban Infrastructure in Smart Cities" ("स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मार्ट सिटीज़") एनसीपीईडीपी और एफआईसीसीआई।
- नीति आयोग 2021, "Reforms in Urban Planning Capacity in India" ("भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार"), भारत सरकार।
- ओईसीडी 2018, "Bridging the Digital Gender Divide" ("डिजिटल जेंडर की खाई को पाटना)"। ओईसीडी।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च 2020, "National Family Health Survey 5" ("राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5") पीआरएस।
- फड़के, खान, रानाडे 2011 द्वारा लिखित और पेंगुइन बुक्स इंडिया द्वारा प्रकाशित, “Why Loiter? Women and Risk on Mumbai Streets” (वाइ लॉइटर? वुमन एडं रिस्क ऑन मुंबई स्ट्रीट")।
- पॉज़र्नी 2016, "Gender roles and opportunities for women in urban environments", ("शहरी वातावरण में महिलाओं के लिए लैंगिक भूमिकाएं और अवसर"), जीएसडीआरसी।
- राइजिगं फ्लेम एडं साइट सेवर्स 2020, “Neglected and Forgotten: Women with Disabilities during Covid Crisis in India” ("उपेक्षित और भूल गए: भारत में कोविड संकट के दौरान विकलांग महिलाएं "): राइजिंग फ्लेम एंड साइट सेवर्स ।
- सियोल सॉल्यूशन 2014। “Women Friendly City Project” (वुमन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट"), सियोल: वुमन एंड फैमिली पॉलिसी अफेयर्स ऑफिस।
- शाह, विश्वनाथ, व्यास और गडेपल्ली 2017. “Women and Transport in Indian Cities”, New Delhi:Institute for Transportation and Development Policy and Safetipin. ("भारतीय शहरों में महिला और परिवहन", नई दिल्ली : परिवहन और विकास नीति और सफेतीपिन संस्थान।
- शेली सी 2017, “Design and Society: Social Issues in Technological Design, Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics 36” (144), Springer International Publishing. ("डिज़ाइन एडं सोसाइटी: सोशल इश्यूज़ इन टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन, स्टडीज़ इन एप्लाइड फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी एंड रैशनल एथिक्स 36" (144), स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग।
- सिंह, रविशंकर और पिल्लई 2020, "Women and Work: How India fared in 2020?" (" वुमन एडं वर्क : हाउ इंडिया फेयर्ड इन 2020?), आईडब्ल्यू डब्ल्यू एजीई।
- स्नाइडर और टेकेडा 2008। "Implications for Bank Operations" ("इंप्लिकेशन फॉर बैंक ऑपरेशन्स"). विश्व बैंक।
- सुब्बाराव और राव 2013. ‘Trip Chaining Behaviour in Developing Countries: A Study of Mumbai Metropolitan Region, India’ (2013) 53 European Transport. ("ट्रिप चेनिंग बिहेवियर इन डेवलपिंग कंट्रीज़: एस्टडी ऑफ मुंबई मेट्रोपोलीटन रीजन, इंडिया" (2013) 53 यूरोपियन ट्रांसपोर्ट
- संयुक्त राष्ट्र 2008। “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” ("कंवेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबेलिटीज़"), न्यूयॉर्क: यूएन सीआरपीडी।
- संयुक्त राष्ट्र डीईएसए. 2018 “2018 Revision of World Urbanization Prospects” (" 2018 रिविज़न ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रोसपेक्टस"), न्यूयॉर्क: यूएन डीईएसए।
- यूएनडीपी 2018, “Disability Inclusive Development in UNDP” ("डिसिबेलिटी इंकल्यूज़िव डेवेलपमेंट इन यूएनडीपी"), न्यूयॉर्क: यूएनडीपी

- यूएनएफपीए 2018, “Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights Based and Gender Responsive Services to Address Gender Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights” : UNFPA and Women Enabled International. ("वुमन एंड यंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ : गाइडलाइन्स फॉर प्रोवाइडिंग राइट्स बेस्ड एंड जेंडर रेसपॉन्सिव सर्वविसिज़ टू एड्रस जेंडर बेस्ड वाइलेंस एडं सेक्सुअल एडं रिप्रोडक्टिव हेल्द एडं राइट्स": यूएनएफपीए एंड वुमन इनेबल्ड इंटरनेशनल.)
- यूएन हैबिटेट 2020. "द न्ययू अर्बन एजेंडा इलस्ट्रेटेड", नैरोबी: यूएन हैबिटेट।
- यूनओडीसी 2018. “Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls” ("ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड: जेंडर-रिलेटिड किलिंग ऑफ वुमन एंड गर्ल्स "), वियना: यूएनओडीसी।
- यूएन वुमन. 2021. “Experiences of women with disabilities in the Asia-Pacific region during COVID-19”.("एक्सिरियंसिज़ ऑफ वुमन विद डिसेबिलिटीज़ इन द एशिया-पेसिविक रीज़न ड्यूरिंग कोविड- 19"). Brief No. 1. Briefs on women with disabilities: UN woman (ब्रीफ न. 1. ब्रीफ ऑन वुमन विद डिसेबिलिटीज़: यूएन वुमन।
- विशाखा 2021। "मेकिंग ए फेमिनिस्ट सिटी: प्लानिंग सेफ्टी एंड ऑटोनॉमी फॉर वीमेन", बेंगलुरु: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी।
- विशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रथा, और दस्तीदार 2022।“Beyond Reasonable Accommodation: Making Karnataka’s Cities Accessible by Design to Persons with Disabilities”, Bengaluru:Vidhi Centre for Legal Policy. ("बियॉन्ड रीज़नेबल एकोमेडेशन: मेकिंग कर्नाटकाज़ सिटीज़ एक्सेसेबल बाय डिज़ाइन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़", बेंगलुरू: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी)
- वॉटर एड 2017. “Gender Equality and Disability Inclusion within Water, Sanitation and Hygiene”, London: Water Aid. ("जेंडर इक्युएलिटी एंड डिसेबिलिटी इंकल्यूज़न विदिन वॉटर, सेनिटेशन एंड हाइजीन", लंडन: वॉटर एड)
- वीज़मैन 1981। “Women’s Environmental Rights: A Manifesto”, Making Room: Women and Architecture 1, New York: Heresies Magazine .("वुमन्स एंवायरमेंटल राइट्स: ए मैनिफेस्टो", मेकिंग रूम: वुमन एंड आर्किटेक्चर 1, न्यूयॉर्क: हेरिसीज़ मैगज़ीन)
- डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) 2002. “The International Classification of Functioning, Disability and Health”: WHO ("द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंकशनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ" : डब्ल्यूएचओ)
- डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक 2011। " “World Report on Disability”: WHO, World Bank.(वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी": डब्ल्यू एचओ, विश्व बैंक)।
- वीमेन एनेबल्ड इंटरनेशनल 2017, Women Enabled International Comments on Draft CEDAW General Recommendation on Gender Related Dimensions of Disaster Risk Reduction in a Changing Climate”: Women Enabled International. ("वीमेन एनेबल्ड इंटरनेशनल कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) जनरल रिकमेंडेशन ऑन जेंडर रिलेटेड डाइमेंशन्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन ए चेंजिंग क्लाइमेट": वीमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल।)
- Women with Disabilities India Network 2019, "Submission of Alternative Report (Article 6) To the Committee on the Rights of Persons with Disabilities : India 2019", Women with Disabilities India Network (वुमन विद डिसेबिलिटीज़ इंडिया नेटवर्क 2019, "सबमिशन ऑफ ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट (आर्टिकल6) टू द कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ : इंडिया 2019" वुमन विद डिसेबिलिटीज़ इंडिया नेटवर्क)
- वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) 2020। “Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning Design”, Washington: World Bank. ("हैंडबुक फॉर जेंडर-इंक्ल्यूज़िव अर्बन प्लैनिंग डिज़ाइन", वाशिंगटन: विश्व बैंक।)
- वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) 2019। “Brief on violence against women and girls with disabilities”, Violence Against Women and Girls (VAWG) Resource Guide. ("ब्रीफ ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़", वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स (VAWG) रिसोर्स गाइड।)
- वैपलिंग, शजोएड्ट और सिबुन 2021, "Social Protection and Disability in India". Development Pathways India. (सोशल प्रोटेक्शन एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया". डेवलपमेंट पाथवेज़ इंडिया.)

स्वीकृतियाँ

हम स्नेहा विशाखा, दामिनी घोष और नम्रता मुरुगेशन (विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, कर्नाटक) के आभारी हैं कि उन्होंने नीति संक्षिप्त को लिखा और डोमेन विशेषज्ञों और विकलांग व्यक्तियों के संगठनों के साथ परामर्श प्रक्रिया का नेतृत्व किया। इस दस्तावेज़ को तैयार करने में उनकी सहायता के लिए हम विधि की प्रशिक्षु अनुसंधान टीम- रानू तिवारी, नंदिनी जीवा और प्रज्ज्वल श्रीवास्तव के बहुत आभारी हैं।

हम विशेष रूप से डॉ. ध्वनि मेहता (विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी) और निधि गोयल (राइजिंग फ्लेम) द्वारा नीति संक्षिप्त की समीक्षा करने के लिए तथा बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए दिए गए सहयोग की सराहना करते हैं।

हम बृंदा शास्त्री (वास्तुकार), श्रेया शेट्टी (वास्तुकार), मीरा जे (निमहंस), शिवराम देशपांडे (समर्थनम ट्रस्ट), राहुल बजाज (दिव्यांगता अधिकार वकील, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी), सोबिया रफीक (स्थानीय संवेदन) को उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पारुल कुम्था (नेचर नर्चर आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स), आशा हंस (शांता मेमोरियल रिहैबिलिटेशन सेंटर), वी. बसावराजू (दिव्याांग व्यक्तियों के भूतपूर्व राज्य आयुक्त, कर्नाटक), कविता कृष्णमूर्ति (किलिकिली), काव्या पूर्णिमा बालाजेपल्ली (एनसीपीईडीपी - जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी), अजय सूरी (इनक्लूसिव सिटीज सेंटर, रा.न.का.सं.), सौम्या टी गुप्ता (हमसफर ट्रस्ट), अपूर्व कुलकर्णी (ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट), शंपा सेनगुप्ता (श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स सेंटर), वैष्णवी चिदबरनाथन (ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन), उत्सव चौधरी (रा.न.का.सं.) और राधिका कौल बत्रा, रंजिनी मुखर्जी और आरती ठाकुर (यूएनआरसीओ) को नेशनल एक्सपर्ट्स राउंडटेबल कंसलटेशन और सत्यापन कार्यशाला के दौरान मसौदा नीति संक्षिप्त पर उनकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम नीति संक्षिप्त को अंतिम रूप देने में उनके इनपुट के लिए शिवानी गुप्ता (सीबीएम अंतर्राष्ट्रीय), मोहम्मद आसिफ इकबाल (पीडब्ल्यू सी), माधुरी दास (यूनिसेफ), आदिश्री पांडा और पारुल शर्मा (यूएन-हैबिटेट) के भी आभारी हैं।

United Nations

भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन शामिल हैं जिन्हें भारत में सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। निवासी समन्वयक, सरकार के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नामित प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के शासनादेव की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के टीम का नेतृत्व करते हैं, जबकि पूरे संयुक्त राष्ट्र के परिवार के समर्थन और मार्गदर्शन पर आकर्षित होते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया india.un.org वेबसाइट पर विजिट करें

National Institute of Urban Affairs

1976 में स्थापित, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) को शहरीकरण से संबंधित कार्यों पर अनुसंधान और अभ्यास के बीच के अंतराल को समाप्त करने और देश की इन शहरी चुनौतियों का समाधान करने के उपायों और तंत्र का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। 40 से अधिक वर्षों से, रा.न.का.सं. तेजी से विकसित हो रहे शहरी भारत के लिए शहरी आख्यान के निर्माण में और कभी-कभी योगदान देने में अग्रणी रहा है। संस्थान विभिन्न पैमानों पर शहरी विमर्श का निर्माण करने के लिए शहरी भारत के प्रमुख क्षेत्रों को सामने लाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

इसने शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन, नीति समर्थन और क्षमता निर्माण में अपनी दक्षताओं का उपयोग किया है और भारत में सतत, समावेशी और उत्पादक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। यह भारत में शहरी विकास के लिए एक विचारशील लीडर और ज्ञान केंद्र के रूप में उभरा है और भारत की शहरी परिवर्तन यात्रा के लिए सहयोग और साझेदारी के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठनों द्वारा इसकी माँग की जाती है। रा.न.का.सं. अपनी सभी पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समावेशिता के माध्यम से सशक्तिकरण

Contact us: National Institute of Urban Affairs, 1st Floor, Core 4B, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -110003, India
Telephone: (91-11) 24617517, 24617543, 24617595 • Email: director@niua.org, thebasiicproject@niua.org, uchoudhury@niua.org
• Website: www.niua.org @Niua_India